प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 31 जुलाई, 2015

विषय-जिला कारागार, इटावा, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर एवं सम्बन्धित जनपद न्यायालयों में (गाजीपुर को छोड़कर) वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणनों की प्रशासकीय स्वीकृति/वित्तीय अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-665/नम-2, दिनांक 12 जनवरी, 2015 एवं पत्र संख्या-8917/नम-2, दिनांक-17 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयांकित जिला कारागारों/जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-1575(1)/22-4-2012-119(ब)/2000टीसी-8, दिनांक 23.01.2013 द्वारा रू0 41.24 लाख प्रति कारागार/जनपद न्यायालय की दर से प्रदान की गयी थी। मूल स्वीकृति लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अधिकांश धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणनों को व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 430.42 लाख की लागत पर निम्न विवरणानुसार अनुमोदित किया गया है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जिला कारागार/जनपद न्यायालयों के नाम जहाँ वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	जिला कारागार/जनपद न्यायालय, इटावा	41.24	86.05
2	जिला कारागार/जनपद न्यायालय, फिरोजाबाद	41.24	81.57
3	जिला कारागार/जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर	41.24	89.30
4	जिला कारागार/जनपद न्यायालय, मैनपुरी	41.24	85.40
5	जिला कारागार/जनपद न्यायालय, मुजफ्फनरगर	41.24	61.54
6	जिला कारागार, गाजीपुर	22.43	26.56
	योग-	228.63	430.42

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, इटावा, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर एवं सम्बन्धित जनपद न्यायालयों में (गाजीपुर को छोड़कर) वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणनो जिनकी अनुमोदित लागत रू0 4,30,42,000/-(रूपया चार करोड़ तीस लाख बयालिस हजार मात्र) है, की पुनरीक्षित प्रशासकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति/वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों की अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणनों में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार एवं योगफल में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

3- पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष परियोजनाओं की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

4- व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.07.2015 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-159/2015/1018(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इटावा, फिरोजाबाद, बुलन्दशहर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in